dure. The Government of Andhra Pradesh has been requested to furnish clarifications in response to the Memorandum submitted by them. No Memorandum has been received from the other States in the wake of cyclone.

(e) It is primarily the responsibility of the State Governments concerned to undertake relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities from the allocation under Calamity Relief Fund (CRF). The allocation made to Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa, Rajasthan and West Bengal under CRF during 1998-99 and the Central share is indicated below:

(Rs. in crore)

	Calamity Relief Fund Allocation	Central share
Andhra Pradesh	137.73	103.30
Gujarat	154.83	116.12
Orissa	54.36	40.77
Rajasthan	198.56	148.92
West Bengal	56.92	42.69

The entire Central Share has been released to these States.

(f) The India Meteorological Department (IMD) Centre in Gujarat has been strengthened. The Govt. of Gujarat has prepared State Level and District Level Contingency Plans to deal with cyclones.

यूरिया की कीमत में वृद्धि से यूरिया की बिक्री और खपत पर प्रभाव

1740. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरिया की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इससे यूरिया की खपत और बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यूरिया की कीमतों में पिछली बार वृद्धि कब की गई थी; और

(घ) क्या इस मूल्य वृद्धि से यूरिया की खपत में गिरावट आने की आशंका है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) दिनांक 29.1.1999 से यूरिया के अधिकतम मूल्य 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिए गए हैं।

(ख) और (घ) यूरिया के मूल्य में वृद्धि से संभवतया यूरिया की खपत और बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) दिनांक 21.2.1997 से यूरिया का अधिकतम मूल्य आखिरी बार 2760 रुपए से बढ़ाकर 3660 रुपये प्रति मीटरी टन हो गया। 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से 4160 रुपये प्रति मीटरी टन की मूल्य वृद्धि जो 1.6.98 से लागू हुई थी, दिनांक 13.6.1998 को वापिस ले ली गई।

औषधीय दृष्टि से मूल्यवान वानस्पतिक उद्यान

1741. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधीय बाग लगवाकर वानस्पतिक उद्यानों के विकास के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के उद्योगों का विकास करने वालों को कोई विशेष सहायता या प्रोत्साहन देगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय आठवीं योजना से ही 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से "औषधीय तथा सुगंधित पादवों का विकास" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत 16 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जड़ी-बूटियों के बगीचों की स्थापना के लिए 75,000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा इनकी देख-भाल के लिए 35,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार औषधीय पौधों की नर्सरी की स्थापना के लिए एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर तथा इनकी देख-भाल के लिए 35,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता दी जा रही है। यह योजना 1997-98 के दौरान जारी थी तथा इसे 1998-99 में भी चलाया जा रहा है। भारतीय